International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(7): 16-18
Received: 22-04-2024
Accepted: 26-05-2024

डॉ. मनोहर कुमार
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, के.के.एम. कॉलेज, पाकुड (एस. के. एम. यू., दुमका झारखण्ड की अंगीभूत इकाइ, झारखण्ड, भारत

Corresponding Author:
डॉ. मनोहर कुमार
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, के.के.एम. कॉलेज, पाकुड (एस. के. एम. यू., दुमका झारखण्ड की अंगीभूत इकाइ, झारखण्ड, भारत

नई शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना

डॉ. मनोहर कुमार

सारांश
भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में इस विचार पर काफी जोर दियागया कि भारत की बहुभाषी प्रकृति हमारा एक बड़ा आधार है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर ही विद्यार्थियों को स्थानीय और मातृभाषाओं में शिक्षण सामग्री और अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रयासकिया हैं। बच्चे अपनी भाषा में शुरूआती ज्ञान अर्जित करने के बाद स्कूली शिक्षा में अपने ज्ञान को उसी गति से विस्तार दे पाएं, इसके लिए स्थानीय भाषा के 52 प्राइमर तैयार किए गए है। उपरोक्त विषय एवं तथ्य के आलोक में यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत का स्वन साकार करने में सफल होगी। यह नीति भारत की शिक्षा नीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। विश्व जगत के लिए नई शिक्षा नीति ईष्या एवं आकर्षण का केन्द्र होगा।

कुटशब्दः शिक्षा, विकसित भारत, शिक्षा निति

प्रस्तावना
भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में इस विचार पर काफी जोर दियागया कि भारत की बहुभाषी प्रकृति हमारा एक बड़ा आधार है। और राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए इसके समुचित उपयोग की आवश्यकता है। इस नीति में हर स्तर पर बहभाषावाद को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, ताकि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में अध्ययन का अवसर मिल सके। सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता इस बहुभाषी संस्कृति को बढ़ावा देगीऔर यह विकसित भारत के निर्माण में बेहतर योगदान दे सकेगी। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर ही विद्यार्थियों को स्थानीय और मातृभाषाओं में शिक्षण सामग्री और अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रयासकिया हैं। बच्चे अपनी भाषा में शुरूआती ज्ञान अर्जित करने के बाद स्कूली शिक्षा में अपने ज्ञान को उसी गति से विस्तार दे पाएं, इसके लिए स्थानीय भाषा के 52 प्राइमर तैयार किए गए है। स्थानीय भाषाअें में पठन सामग्री के रूप में तैयार इन प्राइमरों का उद्देश्य बच्चों को न केवल पढ़ने लिखने में भाषा की दक्षता प्रदान करना है, बल्कि उनमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावाव देना भी है।

अभी 17 राज्यों की 52 स्थानीय भाषाओं में ये प्राइमर तैयार हुए हैं। इनमें आदिवासियों एवं जनजातियों को ध्यान में रखकर उनके समाज की भाषाओं को भी शामिल किया गया है। इस पहल से बच्चों में विषय के प्रति अभिरूची और स्पष्टता बढ़ेगी। यह बच्चों के ज्ञानवर्धन के साथ–साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी बाजी पलटे वाली साबित होगी। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने और हमारे देश के उज्जवल भविष्य को आकार देने में एक मतबूत नींव रखने की मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये प्राइमर उन बच्चों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी होगें, जिन्हें ज्ञान अर्जन के क्रम में विभिन्न भाषाओं से गुजरना पड़ता है। शिक्षार्थियों के लिए ये प्राइमर किसी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों एवं प्रतीकों का उच्चारण करने पहचानने और समझने की कुंजी के रूप में कार्य करेंगे। यह बच्चों को इन अक्षरों के एक या अधिक सेटों के संयोजन से बने वाक्यों के अर्थो से भी उनका परिचय कराएंगे।

आमतौर पर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरूआत उनकी स्थानीय भाषा से होती है। स्कूल जाने के पश्चात् उन्हें अपनी भाषा–बोली अथवा राज्य विशेष की प्रमुख भाषा में पढ़ाई करनी पड़ती हैं ऐसे में उन्हें शुरूआत में ही दिक्कत का सामना करना पड़ता हैं यदि स्कूल में ही बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में समझने की सुविधा प्राप्त हो जाए, तो मूल विषयों के प्रति उनकी समझ और बढ़ेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई में ये प्राइमर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। प्राइमर शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम होने जा रहा है। ये मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा तक उनकी पहुँच बनाएंगे। इससे बच्चों में गहरी समझ के साथ–साथ आजीवन सीखते रहने की क्षमता का विकास होगा। स्वदेशी संस्कृति से भी उनका जुड़ाव बढ़ेगा। प्राइमर तैयार करने के लिए ओडिशा की छह भाषाएं या बोली चुनी गई हैं।

इनमें गदबा, जुआंग, कुई, किसान, संताली ओडिया और सौरा शामिल हैं। असम से आठ भाषओं में प्राइमर बनाए गए हैं, जिनमें असमी, बोड़ो, देओरी, दिमासास, हमार,कार्बी, मिसिंगऔर तिवाको स्थान मिला है। मणिपुर की छह भाषओं अनाल, काबुई (रोंगमई), लियांगमई, मणिपुरी, माओं और तंगखुल को चुना गया है। नगालैंडकी पाँच भाषाओं अंगामी, एओ, खेजा, लोथा और सुमी में प्राइमर बनेहैं। सिक्किम की भूटिया, लेपचा, लिंबू, नेपाली, राई, शेरपा और तमांग समेत सात भाषाओं के लिए प्राइमर बने हैं।

आंध्र प्रदेश की जातपा, कोंड़ा और कोया तो अरूणाचल प्रदेशकी मिशमी, नयिशी, तांग्सा और वांचों के अलावा झारखण्डकी खरिया, कुरूख और मुंडारी के साथ ही कर्नाटक की कोदावा और तुलू में प्राइमर बनाएगएहैं। छत्तीसगढ़ की हल्बी, हिमाचल की किन्नौरी, मध्यप्रदेशकी कोकू,महाराष्ट्र की खानदेशी, मेघालयकी गारो, मिजोरम की मिजो, त्रिपुरा की मोघ और बंगाल की संताली बांग्ला भाषाओं में प्राइमर तैयार किए गए हैं। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण के साथ–साथ राष्ट्र कानिर्माण भी इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माणइसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। देश में आज भी करीब 17 करोड़ बच्चे सामाजिक, आर्थिक और भाषा संबंधी कई अन्य कारणों से पांपरिक तरीके से स्कूली शिक्षा हासिल नहींकर पा रहे हैं। इन्हीं परिशानियों का हल राष्टक्रीय शिक्षा नीति में खोजने का प्रयास किया गया है। प्राइमरों के माध्यम से ज्ञान की राहमें भाषा संबंधी कठिनाई दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय पहले भी ऐसे कई कदम उठा चुका है, जिनकी सहायता से बच्चे शिक्षा और ज्ञान, दोों अर्जित कर सकते हैं। दृष्टि, वाक् शक्ति या सुनने की शक्ति न रखने वाले बच्चों के लिए सरकार–ई–कामिक के रूप में एक पुस्तिका ला चुकी है। प्रिया सुगम्यता ग्राम की यह पुस्तिका बच्चों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है।

प्रत्येक सरकार नीति बनाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उस नीति को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करेन के बाद उस पर शत–प्रतिशत अमल हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों की बुनियादी साक्षरता मजबूत हो, यही हमारा ध्येय है ताकिहम विकसित भारत के लिए एक सशक्त और विपुल ज्ञान से परिपूर्ण पीढ़ी तैयार कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारतीय शिक्षा जगत में कई बड़े बदलाव धरातल पर दिखेंगे। उम्मीद की जा रही है कि नई शिक्षा नीति में दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करतेहुए उच्च शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलाव की गवाह बनेगी। स्नातक प्रोग्राम की पढ़ाई का फ्रेमवर्क पूरी तरह से बदलने जा रहा है। देश केसभी विश्व विद्यालयों में चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नताक प्रोग्राम केलिए विषय, पाठ्यक्रम से लेकर क्रेडिट तक का खाका तैयार किया है। इसे करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नाम दिया गया हैं, वही, छात्रों को कोर एरिया की डिग्री के साथ अपने मनपसंद विषयों को चुनने की आजादी, बीच में पढ़ाई छोड़ने से लेकर विश्वविद्यालय तक कोअपनी सहूलियत के हिसाबसे बदलने (पोर्टेबल फेसिलिटी) का मौका मिलेगा। दिलचस्प यह है कि छात्र जहां पर बीच में पढ़ाई छोड़ेगा. वही से उदसे सात साल केभीतर जारी करने का विकल्प भी मिलेगा। स्कूली शिक्षा केबाद अब उच्च शिक्षा भी लर्निंग आउटक्रम पर आधारित होगी। हर साल ज्ञान, कौषल और सक्षमता पर आधारित परीक्षा मूल्यांकन होगा। खासबात यह है कि प्रति सेमेस्टर कम से कम 20 क्रेडिट लेने अनिवार्य होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सोमवार को करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉच किया किया है। इसमें रोजगार से जोड़ने के लिए ववोकेशनल और इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। छात्र पहले वर्ष की पढ़ाई में 40 क्रेडिट आैर एक साल का वोकेशनल कोर्स में चार क्रेडिट लेता है तो बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद तीन साल के अंदर वो दोबारा उसी डिग्री प्रोग्राम की आगे की पढत्राई से जुड़ सकेगा, जबकि अधिकतम सात साल के भीतर एंटी–एग्जिट की सुविधा मिलेगी। देशभर के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर और च्वॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागूहै। नए फ्रेमवर्क में सेमेस्टर में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीबीसीएस को इनोवेशनऔर चलीलेपन के साथ संशोधित किया गयाहैं एक सेमेस्टर 90 दिन का होगा। नए नियमों के तहत तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 120 क्रेडिटऔर चार वर्षीय प्रोग्राममें 160 क्रेडिट लेने अनिवार्य होंगे। जबकि प्रति सेमेस्टर कम से कम 20 क्रेडिट जरूरी रहेंगे। छात्र को हरसाल कम से कम 40 क्रेडिट लेने होंगे। इनमें कॉमन कोर्सके 24 क्रेडिट तो इंट्रोडक्टरी कोर्स के 18 क्रेडिट होंगे। पहले साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरेसाल में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री व रिसर्च डिग्री मिलेगी। नौकरी पेशा या अपना कामकाज कर रहे लोगों को भी डिग्री पूरी करने का अब विकल्प मिलेगा। पारिवारिक या किसी अन्य दिक्कत के चलते जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन्हें भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। मसलन कोई ऑटोमोबाइल ,इलीक्ट्रिल,मैकेनिकल समेत दूसरे प्रोफेशनल कामों में लगे लोगों का बीटेक या बीई जैसी तकनीकी डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई का मौका मिलेगा। इसके लिए यूजी प्रोग्राम के दूसरे वर्ष में विकल्प रहेगा। हालांकि ऐसे लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक परीक्षा पास करनी होगी।

नए जमाने के इस पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान, प्राफेशनल नॉलेज, स्किल के अलावा छात्रों को मेकओर भी किया जाएगा। इसमें उन्हें खासतौर पर नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा, इंटर्नशिप यदि की अनिवार्य पढ़ाईऔर फ्रैक्टिकल व फील्ड वर्क करना होगा। इसका मकसद उन्हें घर, परिवार, समाज, देश के साथ काम के दौरान सहकर्मियों से व्यवहार के भी गुरू मिलेंगे। चौथे, पाँचवे और डठे सेमेस्टर में एक मुख्य विषय लेना होगा और दो छोटे यानी माइनर सब्जेक्ट का विकल्प मिलेगा। चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम के छात्रों को अब लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान देना होगा। इसी केतहत पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गयाह" छात्र को दिक्कतों का समाधान करने का कौशल क्रिएटिव थिंकिंग, कम्यूनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, विभिन्न देशों, राज्या के लोगों को जानना, मानवीय मूल्य, सिद्धांत समेत अनय विषयों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। परीक्षा में भी छात्र का इन्हीं बिन्दुओं पर आकलन किया जाना है। पहले साल की पढ़ाई पुरी करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा, तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर स्नताक डिग्री मिलेगी। इसकेबाद चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम भी इसी से जुड़ जाएग। यदि कोई छात्र ऑनर्स करना चाहता होगा तो उसको चौथे साल की पढ़ाई करनी होगी। ऑनर्स की पढ़ाई का विकल्प सभी छात्रों के सामने खुला रहेगा। हालोंकि तीसरे वर्ष की डिग्री प्रोग्राम की पढत्राई करनेपर उनके पास 75 फीसदी अंक जरूरी होंगे। पाँचवे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर पीजी डिप्लोमा और छठे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर उसे स्नातकोत्तर की डिग्री मिल जाएगी।

बीए, बीकॉम, बीसएसीवाले छात्र दूसरे और तीसरे वर्ष में मल्टीडिस्पलनेरी की पढ़ाई कर सकेंगे। मल्टीडिस्पलनेरी की पढ़ाईके लिए भी परीक्षा आधारित मूल्यांकन से विकल्प मिलेगा। यदि कोई पहले या दूसरे वर्ष किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसकेलिए गर्मियों में दो महीने का ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा यह 10 क्रेडिट का होगा, इसमें रोजगार से जोड़ने पर काम होगा। बहुविषयक में नुचुरल और फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स–कंप्युटर एप्लीकेशन–स्टेटिक्स,

लाइब्रेरीथ–इंफोरमेशन–मीडिया सांइस, कॉमर्स मैनेजमेंट, ह्यूमनाइटिज– शोसल साइंस के कोर्स ग्रुप बनाए गए हैं। सातवें और आठवें सेमेस्टर में छात्र को ऑनर्स और रिसर्च का विकल्प मिलेगा। जिन छात्रों के तीसरे साल में 75 फीसदी अंक होंगे, वे रिसर्च केलिए जा सकेंगे। इसके अलावा 160 क्रेडिट लेने भी जरूरी होगें। पहले छह सेमेस्टर के बाद छात्र रिसर्च एरिया में भविष्य बनानेकेलिए फैसला ले सकेगा। यह पढ़ाई पुरी करने पर छात्र को ऑनर्से विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ऑनर्स लेने वाले छात्रों को एक सेमेस्टर छोटी रिसर्च पर काम करनाहोगा। इसके अलावा एडवांस लेवल पर अपने विषय की पढ़ाई होगी। वहीं रिसर्च एरिया वाले छात्र को एक सेमेस्टर पूरा एडवांस रिसर्च पर काम करना पड़ेगा। डिग्री में अब डिवीजन नहीं ग्रेड होगा। समलन 10 से लेकर 4 तक ग्रेड निधारित किए गए हैं। इसमें 10 को आउटस्टैंडिंग, 9 को एक्सीलेंट 8 को वेरी गुड, 7 को गुड 6–5 को एवरेज और 4 पास की श्रेणी में होगा। इसके नीचे के सभी फेल श्रेणी होगी। कोर एरिया यामेजर कोर्स में तीन वर्षी में 60 क्रेडिट तो चार वर्ष में 80 क्रेडिट, माइनर स्ट्रीम में तीन वर्ष में 24 और 32 क्रेडिट,बहुविषयक में तीन और चार वर्षीयमें 9–9 क्रेडिट समर इंटर्नशिप में तीन व चार वर्षीय में 2 से चार–चार क्रेडिट की जरूरत होगी।

उपरोक्त विषय एवं तथ्य के आलोक में यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत का स्वन साकार करने में सफल होगी। यह नीति भारत की शिक्षा नीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। विश्व जगत के लिए नई शिक्षा नीति ईष्या एवं आकर्षण का केन्द्र होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. इकनूर माया (2017). सेल्फ–वैल्यूज ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स वर्किंग इन तुर्किष पब्लिक स्कूल्स.अकेडमिक जर्नल, 12 (11), 595–603
2. फही पेट्रिक, वू हसिन चिअ्ह, हॉय बेचने के. (2010). इन्डिविडूअल अकेडमिक ऑप्टिमिज्म ऑफ टीचर्स.एनुअल मिटिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी काउन्सिल फॉर एडूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन केलीफॉर्निआ, नवम्बर–2009, पृष्ठ 209–227.
3. गुप्ता, एस.पी. (2006). सांख्यिकीय विधियाँ.शारदा पुस्तक भवन, पब्लिसर्श एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद।
4. गुप्ता (2012). माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के मूल्य लिंग, शिक्षण अनुभवएवं विद्यालय प्रकृति के सन्दर्भ में.अकेडमिकिआ साउथ एथिअन अकेडमिक रिसर्च जर्नल, 2(2).
5. गुप्ता, मंजू (1991). भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास.के. एस.के.पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड़, नई दिल्ली–110002।
6. गहाली, विजया लक्ष्मी (2006). माध्यमिक स्तर के बालकों के अभिभावकों व शिक्षकों द्वारा दिये गये मूल्यों कामहत्व.एजूट्रैक नीलकमल पब्लिकेशन्स, हैदराबाद, 34–38
7. होय वेयने के., टार्टर सी जॉन,होय अनीता वूलफॉल्क (2006). अकेडमिक ऑप्टिमिज्म ऑफ स्कूल्स : एकफोर्स फॉर स्टूडेन्ट अचिवमेन्ट. अमेरिकन एजूकेशनल रिसर्च जर्नल, 43(3), 425–446
8. हामिद अशरफ एण्ड एट अल (2017). टीचर्स कमिटमेंट टू प्रोफेशनल एथिक्स एण्ड देअर इमोशनल इन्टैलीजेन्सः अ रिलेशनशिप स्टडी.कोजेन्ट एजूकेशन जर्नल, 4(1)
9. ह्सु (2010). द रिलेशनशिप बिटविन द इमोशनल इन्टेलीजेन्स, बर्नआउट एण्ड टीचर एफिकेसी अमंग एलीमेन्टरी स्कूल टीचर्स इन ताईवान.लघु शोध प्रबन्ध का ओह्सिउंग विश्वविद्यालय.
10. जूलिडेह फरनक, यशोधरा के. (2008). भारत व ईरान के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक मूल्य आयु एवं शिक्षण विषय के सन्दर्भ में.एजूट्रैक नीलकमल पब्लिकेशन्स, हैदराबाद,वॉल्यूम–8, 34–38.
11. जमशिदि, पूल तथा खोशकोरोदि (2012). विद्यालय शिक्षकों की आत्म–प्रभावकारिता पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव.जर्नल ऑफ बेसिक अप्लाइड साइंस रिसर्च, 2(9),9710–9716.
12. जूड (2011). माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव पर संवेगात्मक बुद्धि एवं लिंग का प्रभाव. पाकिस्तानजर्नल ऑफ सोशल साइंस, 8 (4),159–165
13. केबट, आर.एन. (2007). राष्ट्रीय चेतना का संदेशवाहक : शिक्षक.शिविरा, मासिक पत्रिका, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बीकानेर, पृष्ठ–17.
14. कुमार (2013). वैल्यूज ऑफ सीनियर सैकेण्डरी स्कूल टीचर्स. इण्टरनेशनल इन्डेक्स्ड एण्ड रेफर्ड रिसर्च जर्नल, 111 (34), 72–73.